विचार बिन्दु

हर किसी की निंदा सुन लो, लेकिन अपना निर्णय गुप्त रखो। –शेक्सपियर

सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आंदोलन रत महिला पहलवानों के विषय में पूर्णतया चुप्पी साध रखी है। इन महिला पहलवानों का आंदोलन 23 अप्रैल 2023 से जंतर-मंतर पर चल रहा था और समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन भी लगातार मिल रहा था। ये पहलवान शांतिपूर्वक, जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर जहां प्रधानमंत्री, उनकी सरकार ने किस प्रकार महिलाओं की गरिमा को बचाने और बढ़ाने का काम किया है, उसका बखान कर रहे थे, ठीक उसी समय लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस द्वारा सड़कों पर घसीट कर बलपूर्वक हिरासत में लिया जा रहा था। उनके ऊपर कई प्रकार की धाराएं लगाकर एफ आई आर दर्ज कर ली गई। जहां एक और यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण सिंह पर एफ आई आर दर्ज कराने के लिए महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, वहीं न्याय मांग रही उन महिला पहलवानों को बेइज्जत करते हुए धरना स्थल से उठा लिया गया। उनके तंबू इत्यादि भी हटा दिए और जंतर-मंतर के स्थान को साफ कर लिया गया। न केवल यह, दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि दुबारा उन्हें जंतर-मंतर पर बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद लगातार कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश और हरियाणा में खाप पंचायतों की बैठकें हुई हैं जहां पहलवानों के समर्थन में विभिन्न प्रकार के कदम उठाने की बात की गई है।

अपने साथ दुर्व्यवहार से महिला पहलवान इतने दुखी और क्षुब्ध थे कि उन्होंने अपने सारे जीते हुए मेडल गंगा नदी में प्रवाहित करने का निर्णय ले लिया एवं इस हेतु वे हरिद्वार में हर की पौड़ी तक पहुंच गईं। बाद में किसान नेता नरेश टिकैत आदि ने उन्हें ऐसा करने से रोका और सरकार को कार्रवाई करने हेतु कुछ समय देने की बात कही। उनकी बात को मानते हुए पहलवानों ने अपने मेडल प्रवाहित नहीं किए एवं इस निर्णय को कुछ दिनों के लिए टाल दिया। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ ने भी भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 10 जून तक नहीं कराने पर भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता समाप्त करने की चेतावनी दे डाली। यदि ऐसा हो जाता है तो यह देश के लिए शर्म की बात होगी। भारत के पहलवानों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अंतर्गत भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा एवं वह बिना राष्ट्रीय ध्वज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह सब केवल इसलिए हो रहा है। कि भारत सरकार ने इस पूरे प्रकरण में चुप्पी साध रखी है।

भाजपा की महिला नेता, जिनमें भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी प्रमुख हैं, का कोई बयान इस विषय में नहीं आया है। ये छोटी-छोटी बातों पर बहुत बढ़-चढ़कर के बयान देती रही हैं। हाल ही में भारत सरकार की मंत्री मीनाक्षी लेखी से इस विषय में एक पत्रकार ने टिप्पणी लेनी चाही तो वे भागती नजर आयीं। इस दृश्य को टीवी कैमरा द्वारा कैद कर लिया गया। कोई भाजपा महिला सांसद, अभी तक इस विषय में किसी प्रकार का समर्थन देने के लिए आगे नहीं आई है। यह अवश्य है कि 1983 की क्रिकेट विश्वकप विजेता टीम के सदस्यों ने महिला पहलवानों के समर्थन में अपना बयान जारी किया है। प्रश्न उठता है कि क्या केवल दलीय संबद्धता के आधार पर व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है कि नारी सम्मान की बड़ी बातों को भूलकर उदासीन हो जाते हैं। यह नहीं पता कि महिला पहलवानों के आरोप में कितनी सच्चाई है, किंतु कानूनी आवश्यकता के अनुरूप यौन उत्पीड़न के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर उसे सभी पदों से मुक्त किया जाना चाहिए, तब ही स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच, पहलवानों के आरोपों के बारे में हो सकती है।

एक अँग्रेजी समाचार पत्र 'इंडियन एक्सप्रेस' ने पूरे विस्तार से एफ आई आर का विवरण प्रकाशित किया है कि किस प्रकार एक से अधिक बार बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवान, जिनमें एक नाबालिग भी सम्मिलित है, का यौन उत्पीड़न किया है। प्रकाशित विवरण को पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन सबके बावजूद सत्ताधारी दल द्वारा अपने आरोपी सांसद को बचाने का प्रयास बहुत ही अनुचित है। बृजभूषण सिंह 6 बार से सांसद है और ऐसा माना जा रहा है कि उनका एक जाति विशेष पर बहुत प्रभाव है, जिसके कारण उत्तरप्रदेश की कुछ संसदीय सीटों पर भाजपा को क्षति हो सकती है, यदि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई या उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या वोटों की खातिर महिलाओं की इज्जत को गिरवी रख दिया जाएगा? क्या सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि महिलाओं की गरिमा के प्रति बेरुखी का देश की महिलाओं में कितना विपरीत प्रभाव होगा और उसका किस प्रकार का परिणाम आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है? इस प्रकरण में सरकार को दलीय स्वार्थ से ऊपर उठ कर में कार्यवाही करने की आवश्यकता है। यदि वास्तव में सत्ताधारी दल यह सिद्ध करना चाहता है कि वह महिलाओं के सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध है तो भाजपा नेताओं, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में पूरी पारदर्शिता बरतते हुए, अपनी बात देश के सम्मुख रखनी चाहिए। यदि अब तक उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी होती एवं सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी होती तो शायद इस प्रकार की अटपटी स्थिति सरकार के लिए नहीं बनती।

आशा है, जनभावना का सम्मान करते प्रधानमंत्री जी, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न, सुरक्षा इंतजाम की कमी के कारण हुई रेल दुर्घटना में मारे गए 300 से अधिक यात्रियों के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य की खराब गुणवत्ता के सम्बन्ध में अपने विचार साफ़-साफ़ देश के समक्ष रखेंगे।

प्रधानमंत्री 'मन की बात' देशवासियों से प्रति माह करते हैं, किंतु एक बार भी मन की बात में भी इन पहलवानों के बारे में किसी प्रकार का कोई जिक्र न होना खेद का विषय है। क्या कथनी और करनी में इतना अंतर रखना राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य हो गया है? क्या सारी सामाजिक मर्यादाओं को राजनीति की भेंट चढ़ा दिया जाएगा? वैसे भी, प्रधानमंत्री किसी भी प्रश्न का उत्तर देना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि नौ वर्षों में प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस वार्ता आयोजित नहीं की है। संभवतया यह पहली बार है जब किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री ने देश के मीडिया से बात नहीं की। हां, यह अवश्य है कि वे अपने मीडिया मित्रों को बुलाकर उनसे एक प्रकार से प्रायोजित साक्षात्कार दे देते हैं। अभी तक मीडिया के प्रश्नों से बचते रहे हैं। यह कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि प्रधानमंत्री, वाकपटुता में माहिर माने जाते हैं और उन्हें पत्रकारों के प्रश्नों से बचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वैसे भी लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व जनता के प्रति होता है। मीडिया ही जनता की ओर से नेताओं को प्रश्न करता है।

यदि देश के सम्मुख उत्पन्न कुछ अन्य विषयों की भी बात करें, तो लगता है कि सरकार की प्राथमिकता केवल विशिष्ट वर्ग की आकांक्षा को पूरा करने तक सीमित हो गई है। हाल ही में ओडिशा के बालासोर में जिस प्रकार की भयंकर रेल दुर्घटना हुई और लगभग 300 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 1000 से अधिक घायल हुए, इसी प्रकार के विकास की सोच का परिचायक है क्योंकि हमने बुलेट ट्रेन और आधुनिक सुविधाओं से युक्त वंदे भारत ट्रेन चलाने पर तो बहुत खर्च किया, किंतु सामान्य रेल यात्रियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था के लिए जो आवश्यक प्रावधान किए जाने चाहिए थे वह नहीं किए गए। ट्रेनों को दुर्घटना से बचाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था 'कवच' के नाम से विकसित की गई थी किन्तु उसका पूरी तरह लागू नहीं होना, यही संकेत करता है कि सरकार के लिए सुरक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण दिखावा हो गया है। कुछ-कुछ इसी प्रकार की सोच सेंट्रल विस्टा जैसी विभिन्न परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा करने से परिलक्षित होती है।

सत्ताधारी दल ने सामान्य नागरिक की मूलभूत आवश्यकता शिक्षा और स्वास्थ को तो महत्वहीन बना दिया है। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों से स्पष्ट हो रहा है कि देश के बच्चों को दी देने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पहले से भी कमजोर हुई है। स्पष्ट है कि देश गरीब और अमीर, दो भागों में बट गया है। सरकार की नीतियों के कारण अमीर और अधिक तीव्र गति से अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब हो गए हैं। बाल श्रम निषेध कानून 1986 में बना किन्तु आज भी लाखों बच्चे कचरा बीनते हुए, ढाबों में बर्तन साफ़ करते हुए, चौराहों पर सामान बेचते हुए, घरों पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। 2009 में 'शिक्षा का अधिकार' कानून आने के बाद कामकाजी बच्चों के लिए चल रहा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी बंद कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो बच्चे कुछ शिक्षा प्राप्त कर पा रहे थे वे उससे पूर्णतया वंचित हो गए। होना तो यह चाहिए था कि सभी को समान गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती। स्वतन्त्रता के बाद उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट संस्थान जैसे आई आई टी, आई आई एम आदि तो खोले गए, किन्तु प्रारंभिक शिक्षा की उपेक्षा की गई। फलस्वरुप, देश के नागरिक दो भागों में विभाजित हो गए। एक वह, जिसे सारी सुख-सुविधायें उपलब्ध हैं और दूसरा वह, जिसके पास न दो समय की रोटी का जुगाड़ है, न रहने के लिए घर। शुद्ध पेय जल, स्वास्थ्य, शिक्षा का तो प्रश्न ही नहीं। गरीब-अमीर में बढ़ती खाई का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व में असमानता भारत में सबसे अधिक हो गई है।

चूंकि वर्तमान सरकार का यह अंतिम वर्ष है, यह बहुत अच्छा होगा, यदि प्रधानमंत्री एक संवाद मीडिया के साथ शीघ्र करें और अपनी सरकार की प्राथमिकताएं देशवासियों के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि वे नियमित रूप से जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। ऐसा करते समय उन्हीं बातों का उल्लेख करना चाहिए जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते समय कही थीं। आजकल, रिपोर्ट कार्ड में गिनाया उन कामों को जा रहा है जिसका जिक्र उन्होंने प्रधानमंत्री बनते समय नहीं किया था। यह तो वही बात है कि उत्तर हम वही देंगे जो हमने तैयार किए हैं चाहे प्रश्न कुछ भी क्यों न हो। जनता उन वादों के बारे में जानना चाहती है जो उससे चुनाव से पहले और बाद में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए।

आशा है, जनभावना का सम्मान करते प्रधानमंत्री जी, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न, सुरक्षा इंतजाम की कमी के कारण हुई रेल दुर्घटना में मारे गए 300 से अधिक यात्रियों के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य की खराब गुणवत्ता के सम्बन्ध में अपने विचार साफ़-साफ़ देश के समक्ष रखेंगे। कर्नाटक के चुनाव ने यह तो सिद्ध कर ही दिया है कि अब केवल जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीतना सरल नहीं होगा।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

अयोध्या और हरिद्वार के कथित हिंदू संत आरोपी के साथ क्यों खड़े हैं?

रामगोपाल जाट

भाजपा और सपा के टिकट पर 6 बार सांसद बन चुके भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज एफआईआर की बातें इंडियन एक्सप्रेस अखबार के माध्यम से सामने आने के बाद देशभर में महिला पहलवानों के पक्ष में खड़े लोगों में गहरा रोष है। जिस तरह के आरोप दो एफआईआर में सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि बृजभूषण लड़कियों को किस तरह से दबाव में लेकर उनका शोषण करता होगा। बीते 12 साल से बृजभूषण भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना हुआ है। उसे एक ही सीट से 6 बार लोकसभा चुनाव जीतने का घमंड भी है। उसको इस बात का भी गुमान है कि वह भाजपा ही नहीं, बल्कि जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया, तब समाजवादी पार्टी से जीतकर भी संसद पहुंचा था। बृजभूषण सिंह पर दर्जनों एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट, अपहरण, हत्या, कब्जा करने और दंगे भड़काने के मामले भी दर्ज हैं। इनमें ही एक मुकदमा उस पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाने के दौरान का भी है। यह वह मुकदमा है, जिसके कारण बृजभूषण सिंह उन स्वयंभू हिंदुओं का मसीहा बन गया है, जो बिना सोचे-समझे अंधभक्ति करते हैं, या किसी का अंधविरोध करते हैं। क्या कोई व्यक्ति इसलिये देवता बन जाता है कि उसपर राम मंदिर आंदोलन का केस दर्ज है? दरअसल, उस दौरान कुछ ऐसे लोगों पर भी मुकदमे दर्ज किये गये थे, जो बाबरी मस्जिद को गिराने में थे ही नहीं, बल्कि अन्य किसी कारण से उन पर मुकदमे हो गये थे। कुछ के ऊपर राजनीतिक विद्वेष के कारण मामले दर्ज किये गये थे। क्या इसी आधार पर बृजभूषण देवता बन जाता है कि उस पर राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले का मुकदमा दर्ज हुआ था? या फिर जिस तरह से अयोध्या और हरिद्वार के कुछ स्वयंभू हिंदू संत उसके पक्ष में खड़े हैं, उसके पीछे मासिक वेतन का कारण तो नहीं है? दरअसल, देश में आज भी कई जगह पर अपराधी किस्म के लोगों द्वारा अपना जनपक्ष लेने के लिये कई स्वयंभू साधु-संतों और गरीब लोगों की मासिक तौर पर सहायता के नाम पर धन मुहैया करवाया जाता है।

आपको ध्यान होगा कई राज्यों में धर्मांतरण कराने वालों द्वारा गरीब हिंदुओं को मासिक धन देकर उनका धर्म बदलवाया जाता है। क्या इसका मतलब यह हो जाता है कि वो धर्मान्तरण करवाने वाले लोग देवता हैं? क्या उनके पक्ष में गरीबों की लॉबी खड़ी हो जाये तो धर्मान्तरण को जायज ठहराया जा सकता है? ठीक इसी तरह से धर्म के नाम पर धंधा करने वाले कई ठेकेदार तो बकायदा नेताओं और माफिया द्वारा पोषित होते हैं, और जब उन नेताओं और माफिया पर किसी तरह का संकट आता है, तो वो लोग धर्म की आड़ लेकर बचने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कि अयोध्या के जिन कथित संतों ने बृजभूषण सिंह का पक्ष लिया है, उनका पोषण करने का काम यही करता है। विधानसभा में एक बार योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। ठीक इसी तरह यदि बृजभूषण द्वारा पोषित स्वयंभू संत आज उसके साथ खड़े हैं, तो क्या वो सम्पूर्ण हिंदुओं के संत हो गये? और महिला पहलवान हिंदू नहीं हैं?

मजेदार बात देखिये, जब खिलाड़ियों ने ऐलान किया कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसलिये वो अपने मेडल गंगा में बहा देंगे, तब वहां के कुछ हरिद्वार के पंडे सामने आ गये, और बोलने लगे कि मेडल से गंगा को अपवित्र नहीं होने देंगे। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि एक मेडल पाने के लिये बरसों की तपस्या लगती है, अपने पवित्र रक्त को पानी तरह तरह बहाना पड़ता है, परिजनों की कठोर मेहनत और लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, तब जाकर एक मेडल जीत पाते हैं, यदि ये मेडल ही अपवित्र हैं तो फिर संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो पवित्र होगी। दूसरी बात यह है कि इसी गंगा नदी में ये ही पंडे दिन भर फेंके हुए सिक्के चुनते हैं, तब गंगा अपवित्र नहीं होती? चंद सिक्कों के लिये अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले पंडे जब खिलाडियों के खिलाफ खड़े मिले, तब समझ आ गया कि बृजभूषण ने धर्म के नाम पर अपनी जड़ें कितनी गहरी जमा रखी हैं। तीसरी बात यह है कि इसी गंगा में इन्हीं पड़ों की अनुमति से लाशों को बहा दिया जाता है, तब गंगा अपवित्र नहीं होती है? जब इसी गंगा में इन्हीं पड़ों द्वारा अपना मल मूत्र नलों-नालियों के माध्यम से बहाया जाता है, तब गंगा अपवित्र होती है या पवित्र ही रह जाती है? इन्होंने कहा कि गंगा को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे, तब सवाल यह उठता है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिये इसी गंगा में डुबकी लगाते हैं, तब गंगा पवित्र होती है या अपवित्र? यदि नेताओं के द्वारा अपने पाप धोने के लिये गंगा को दुरुपयोग किया जाता है, तब गंगा गंदी नहीं होती है, तब कठोर तपस्या से कमाये मेडल बहाने से गंगा कैसे अपवित्र हो सकती है?

सरकार और प्रशासन की कमी यह रही है कि पहलवानों द्वारा आरोप लगाने के बाद भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, उनको न्याय पाने के लिये सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तब मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद सवाल यह उठा कि जब मेडल जीतने पर पीएम मोदी इन खिलाड़ियों को अपने घर बुलाते हैं, तब उनकी समस्या सुनने का समय क्यों नहीं देते हैं? क्यों भाजपा की आईटी सेल और कई नेता इन महिला पहलवानों की सोशल मीडिया पर इज्जत उछालने का काम करते हैं? लड़कियों को न्याय दिलाने के लिये आखिर क्यों खापों को सामने आना पड़ता है? क्या देश में कानून का राज समाप्त हो गया है? क्या कानून कई मामलों के एक आरोपी को इसलिये नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वह सत्ताधारी दल का सांसद है? क्या एक माफिया पर सरकार हाथ डालने से इसलिये बचती है, क्योंकि उसकी जाति के वोट छिटकने का डर है?

दर्ज किये गये मुकदमों में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उससे साफ होता है कि आरोप झूठे नहीं हैं। जिस तरह से महिला पहलवानों को गलत जगह पर छूना, उनकी सांस चेक करने के बहाने छाती पर हाथ फेरना, कंधों को पकड़कर दबाना, बाहों में लेकर फोटो खिंचवाना, उनको सप्लीमेंट दिलाने का लालच देकर संबंध बनाने का दबाव बनाना, आगे खिलाने का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर करना। ये ऐसी बातें हैं जो बृजभूषण को जेल भेजने के लिये काफी हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरह से पूरी कहानी का खुलासा किया है, उसके बाद आरोपी के समर्थकों के तेवर भी नरम पड़े हैं, अन्यथा न्याय मांग रही महिला पहलवानों को ही असली आरोपी की तरह सोशल मीडिया पर भला बुरा कहा जा रहा था।

सवाल यह भी उठता है कि 40 दिन बीतने के बाद भी भाजपा के नेताओं के मुंह से यह क्यों नहीं निकल रहा है कि आरोपी को पकड़ा जाना चाहिए, उसके बाद पॉक्सो एक्ट में जांच की जानी चाहिये। वैसे भी पॉक्सो के अनुसार आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी होनी जरूरी है। जब एक महिला के केवल आरोप लगा देने पर आम आदमी को पुलिस तुरंत पकड़ लेती है, तो फिर पॉक्स जैसा मामला होने पर भी बृजभूषण आखिर पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है?

एक सवाल यह उठता है कि महिला पहलवान हरियाणा की हैं, और अधिकांश एक ही जाति की हैं। क्या इसी आधार पर बृजभूषण सिंह को बचाने के लिये सोशल मीडिया की आर्मी खड़ी हो गई है? कल तक देश के लिये दर्जनों गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली महिला पहलवानों की वजह से जिस देश का नाम ऊंचा हो रहा था, आज न्याय की मांग करने पर उन्हीं को एक जाति में बांध दिया जाना कितना उचित है? क्या एक आरोपी के पक्ष में एक जाति विशेष या वर्ग विशेष खड़ा है, वह ठीक है? क्या इसलिये एक आरोपी का बचाव किया जा रहा है कि वह सत्ताधारी दल का सांसद है? क्या इस आधार पर खिलाड़ियों का विरोध किया जा रहा है कि उनके पक्ष में विपक्षी दल खड़े हो गये हैं? सोचो यदि इन ख्यातनाम खिलाड़ियों की जगह यदि कोई आम महिला ने बृजभूषण जैसे माफिया, बाहुबली, धनबली पर आरोप लगाये होते तो उसका और उसके परिवार का क्या होता? क्या ऐसे कोई महिला या लड़की बच सकती थी, जिसका नाम देश दुनिया में ख्याति प्राप्त नहीं होता? जब देश का नाम दुनिया में ऊंचा करने वाली खिलाड़ियों को ही न्याय के लिए बेइज्जत होना पड़ रहा है, तब सोचो आम महिला को पॉक्सो या यौन शोषण के मामलों में कितना न्याय मिलता होगा, और जब आरोपी विधायक, सांसद, रसूखदार, कारोबारी, माफिया, बाहुबली, धनबली हो, तब तो न्याय के बारे में सोचना ही पाप है।

–रामगोपाल जाट,
वरिष्ठ पत्रकार

अनीता ने एवरेस्ट बेस कैंप पर फहराया तिरंगा

डूंगरपुर, (निसं)। डूंगरपुर स्थित प्रतापनगर निवासी अनीता अग्रवाल ने नेपाल में स्थित दुनिया के सबसे ऊँचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर तिरंगा फहराया है। बेस कैंप की ऊंचाई 17,600 फीट है अलग-अलग राज्यों से 17 सदस्यों के साथ 130 किलोमीटर तक का ट्रैक कर 29 मई 23 को इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की इस दुर्गम ट्रैक में 11 दिन का समय लगा। यहां पर इन्होंने भारत माता की जय व वन्देमातरम का नारा लगाया। रास्ते में स्नोफॉल भी हुई वह कभी माइनस तापमान भी रहा। अधिक ऊँचाई होने पर एटीट्यूड सिकनेस के कारण कभी कभी सांस लेने में तकलीफ भी हुई क्योंकि इतनी ऊँचाई पर वनस्पति नहीं होने से ऑक्सीजन की कमी रहती हैं। इससे पहले अनिता माइनस 30 डिग्री तापमान में लेह लद्दाख स्थित जांस्कर रिवर पर चादर ट्रैक 55 किमी तथा माउंट यूनाम पीक तथा 19500फीट तक आरोहण कर चुकी है। तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के साथ चार अन्य कैलाश वह कई अन्य ट्रैक कर चुकी है। उनका कहना है कि विल पावर हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है।

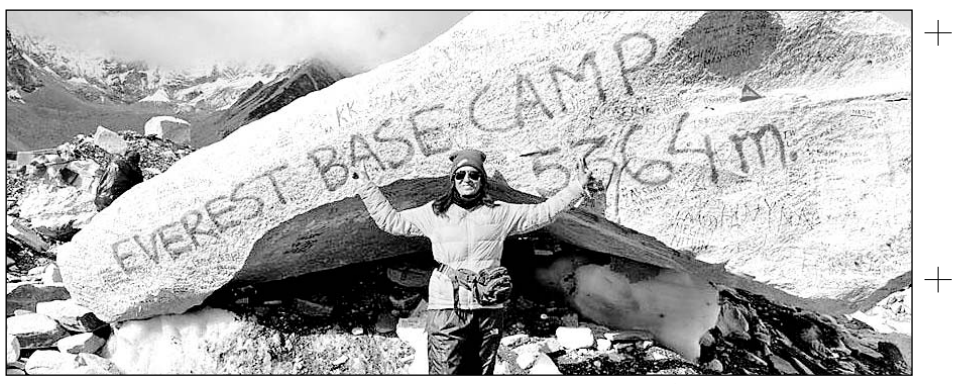

डूंगरपुर स्थित प्रतापनगर निवासी अनीता अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर तिरंगा फहराया।

विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष

चिंतित हैं आज सभी बुद्धिजन, कैसे बचाएं हम अपना पर्यावरण?

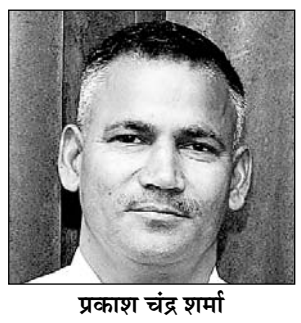

प्रकाश चंद्र शर्मा

पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, 'परि और आवरण' जिसमें परि का मतलब है हमारे आसपास या कह लें कि जो हमारे चारों ओर है। वहीं आवरण का मतलब है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 2023 की थीम की बात करें तो इस साल की थीम- 'प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान रखी गई है, जिसका उद्देश्य प्रकृति को प्लास्टिक मुक्त बनाना और पर्यावरण को बचाना है।

इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी कोटे डी आइवर गणराज्य द्वारा की जा रही है, जिसे पश्चिम अफ्रीका में आइवरी कोस्ट के रूप में भी जाना जाता है। इस साल नीदरलैंड उसका भागीदार होगा।

मानव और पर्यावरण एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। मानव की अच्छी-बूरी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। मानव की बूरी आदतें जैसे पानी दूषित करना, बर्बाद करना, वृक्षों की अत्यधिक मात्रा में कटाई करना आदि पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती है। जिसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना ही पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की और से की गई थी। पर्यावरण दिवस की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से हुई थी। इसी दिन यहां पर दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जिसमें भारत की ओर से तात्कालिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की भी नींव पड़ी थी। जिसके चलते हर साल विश्व पर्यावरण दिवस आयोजन का संकल्प लिया गया।

पर्यावरण के जैविक संघटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े-मकोड़े, सभी जीव-जंतु और पेड़-पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। जबकि पर्यावरण के अजैविक संघटकों में निर्जीव तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे:- पर्वत, चट्टानें, नदी, हवा और जलवायु के तत्व इत्यादि।

सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी पर निर्भर करती और संपादित होती हैं। पर्यावरण के असंतुलन के दो प्रमुख कारण हैं। एक है बढ़ती जनसंख्या और दूसरा बढ़ती मानवीय आवश्यकताएं तथा उपभोक्तावृत्ति। इन दोनों का असर प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है और उनकी वहनीय क्षमता लगातार कम हो रही है। पेड़ों के कटने, भूमि के खनन, जल के दुरूपयोग और वायु मंडल के प्रदूषण ने पर्यावरण को गभीर खतरा पैदा किया है।

दुनिया में पर्यावरण को लेकर चेतना में वृद्धि तो हो रही है परन्तु वास्तविक धरातल पर उसकी परिणति होती दिखाई नहीं दे रही है। चारों ओर पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर लीपा-पोती हो रही है। पर्यावरण आज एक चर्चित और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर पिछले दो-तीन दशकों से काफी बातें हो रहीं हैं। हमारे देश और दुनियाभर में पर्यावरण के असंतुलन और उससे व्यक्ति समाज और राष्ट्र के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा भी बहुत हो रही है और काफी चिंता भी व्यक्त की जा रही है लेकिन पर्यावरण असंतुलन अथवा बिगाड़ को कम करने की कोशिशें उतनी प्रभावपूर्ण नहीं हैं, जितनी अपेक्षित और आवश्यक हैं। इस प्रकार किसी जीव और पर्यावरण के बीच का संबंध भी होता है, जो कि अन्योन्याश्रित है। मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। यह विभाजन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और दशाओं में मानव हस्तक्षेप की मात्रा की अधिकता और न्यूनता के अनुसार है।

पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि मनुष्य को अपनी जीवनशैली के बारे में पुनर्विचार के लिये प्रेरित कर रही है और अब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है पर्यावरण संकट के मुद्दे पर आम जनता और सुधी पाठकों को जागरूक करने की।

–प्रकाश चंद्र शर्मा,
स्वतंत्र पत्रकार एवं लेखक

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 6 जून, 2023

आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2080, पूर्वषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 11:13 तक, शुक्ल योग रात्रि 1:54 तक, वणिज करण दिन 2:20 तक, चन्द्रमा रात्रि 4:40 से मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कर्क, बुध-मेष, गुरू-मेष, शुक्र-कर्क, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज राजयोग सूर्योदय से रात्रि 11:13 तक है। आज भद्रा दिन 2:20 से रात्रि 12:51 तक है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:01 से 10:43 तक, लाभ-अमृत 10:43 से 2:07 तक, शुभ 3:50 से 5:32 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:14

मेष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों से आपसी अनबन बढ़ सकती है और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिल सकती है। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

सिंह
परिजनों के व्यवहार के कारण मन व्यथित रहेगा। आपसी वैमनस्यता के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी।

कन्या
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक और सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला
व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
आर्थिक कारणों